राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या 1496/2012

हरि शंकर बंसल पुत्र श्री. राम दयाल बंसल, निवासी मानव भारती स्कूल के पास, नीमदा गेट, भरतपुर (राजस्थान)

----दावेदार-अपीलार्थी

बनाम

1. नारायण सिंह पुत्र श्री. हरेंद्र सिंह, निवासी सिमको लीवर कॉलोनी, भरतपुर (राजस्थान)
2. सुखवीर सिंह पुत्र हरेन्द्र सिंह, निवासी #69, कृष्णा नगर, भरतपुर (राजस्थान)
3. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय, निधि भवन के पास, हाई कोर्ट सर्कल, जयपुर अपने क्षेत्रीय प्रबंधक के माध्यम से।

----गैर-दावेदार-प्रत्यर्थीगण

अपीलार्थी (गण) की ओर से	:	सुश्री चेल्सी गंगवाल एवं
		श्री आकर्ष गोठवाल के लिए
		श्री वीरेन्द्र अग्रवाल
प्रत्यर्थी (गण) की ओर से	:	श्री रिज़वान अहमद

माननीय न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढंड

<u>आदेश</u>

<u>18/02/2022</u>

<u>रिपोर्टेबल</u>

अपीलार्थी द्वारा वर्तमान अपील मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 173 के तहत मोटर दुर्घटना दावा सिविल विविध(एमएसी) केस संख्या 266/2004 में न्यायाधिकरण (अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक संख्या 1) भरतपुर (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण ' के लिए) न्यायलय द्वारा दिनांक 21.02.2012 के पारित निर्णय और पंचाट के विरूद्ध दायर की गई है जिसके तहत, न्यायाधिकरण ने दावेदार-अपीलार्थी को 5,22,950/- रुपये की राशि का पंचाट सुनाया है।

विद्वान न्यायाधिकरण ने मुद्दे तय करने, रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों का मूल्यांकन करने और दोनों पक्षों को सुनने के बाद, दावेदार-अपीलार्थी की दावा याचिका का निर्णय किया और अपीलार्थी-दावेकर्ता के पक्ष में विभिन्न मदों के तहत 5,22,950/- रुपये के मुआवजे का पंचाट दिया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दावेदार 83.2 प्रतिशत स्थायी विकलांगता का शिकार है और दुर्घटना की तिथि पर उसकी उम्र लगभग 45 वर्ष थी। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि दावेदार-अपीलार्थी 152 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहा। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि विद्वान न्यायाधिकरण ने बिना किसी आधार के केवल यह कहकर कि डॉक्टर की जांच नहीं की गई थी, दावेदार की विकलांगता 60% निर्धारित करने में गलती की है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि जब तीन डॉक्टरों के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता प्रमाणपत्र रिकॉर्ड पर उपलब्ध था, तो स्थायी विकलांगता प्रमाणपत्र को सिद्ध करने के लिए डॉक्टर की जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

अपने तर्कों के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय द्वारा सिविल विविध 2018 की अपील संख्या 3537 "पप्पू सैनी बनाम सुमेर सिंह गुर्जर और अन्य में पारित एक निर्णय पर भरोसा जताया जिसमें इस न्यायालय ने माना है कि जब मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणपत्र जारी किया गया हो तो डॉक्टर को स्थायी विकलांगता प्रमाणपत्र सिद्ध करने के लिए जांच करने की आवश्यकता नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि माना जाता है कि दावेदार की उम्र 45 वर्ष थी, अतः, 14 का गुणक लागू किया जाना चाहिए था, लेकिन बिना किसी आधार के, विद्वान न्यायाधिकरण ने 13 का गुणक लागू किया है।

विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि दावेदार की अपनी दुकान थी और वह पर्यटन और यात्रा का व्यवसाय भी करता था और 83.2 प्रतिशत स्थायी विकलांगता के कारण, वह अपना व्यवसाय और दैनिक गतिविधियाँ करने में सक्षम नहीं है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने एकलपीठ में इस न्यायालय द्वारा सिविल विविध अपील संख्या 4615/2017 "लीलाराम बनाम देशराज एवं अन्य" में 09.12.2021 को पारित निर्णय पर भरोसा जताया, जिसमें घायल की 90 प्रतिशत विकलांगता थी और इस

न्यायालय ने जीवन में सुविधाओं के नुकसान के लिए 3,00,000/- रुपये का मुआवजा दिया।

अंत में, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि *सरला वर्मा बनाम दिल्ली परिवहन निगम: (2009) 6 एससीसी 121* के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार, दावेदार भविष्य की संभावनाओं के लिए मुआवजे की 25 प्रतिशत राशि का भी पात्र है।

इसके विपरीत, प्रत्यर्थी-बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विद्वान न्यायाधिकरण ने दावेदार-अपीलार्थी की दावा याचिका पर निर्णय लेते समय, मामले में उपलब्ध साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के बाद, मुआवजे की राशि की गणना करते समय कारकों को सही ढंग से ध्यान में रखा है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि दिनांक 21.02.2012 के निर्णय में इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

हालाँकि, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता, इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों "पप्पू सैनी" (सुप्रा.), "सरला वर्मा" (सुप्रा.) और "लीलाराम" (सुप्रा.) के आलोक में वर्तमान मामले में पंचाट की पुनः गणना के संबंध में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई दलीलों का खंडन करने की स्थिति में नहीं हैं।

मैंने बार में अधिवक्ता द्वारा की गई प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार किया है और दिनांक 21.02.2012 के निर्णय के साथ-साथ रिकॉर्ड पर उपलब्ध अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों का भी अध्ययन किया है। यह विवाद नहीं है कि दुर्घटना के समय दावेदार की उम्र 45 वर्ष थी, अतः, विद्वान न्यायाधिकरण 13 के गुणक को लागू करने में सही नहीं था और दावेदार की उम्र को देखते हुए, 14 का गुणक लागू होता है।

विद्वान न्यायाधिकरण ने बिना किसी आधार के दावेदार की विकलांगता 60 प्रतिशत निर्धारित करने में गलती की है, जबकि दावेदार के विकलांगता प्रमाणपत्र में यह दर्शाया गया है कि 83.2 स्थायी विकलांगता है और विकलांगता प्रमाणपत्र तीन डॉक्टरों के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया था। विद्वान न्यायाधिकरण ने दावेदार को 25 प्रतिशत भविष्य की संभावनाएं न देकर भी गलती की है और अस्पताल में बिताए गए 152 दिनों के इलाज के लिए एक पैसा भी नहीं दिया है।

जबकि डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित स्थायी विकलांगता 83.2% है, लेकिन यह किसी भी तरह से पर्याप्त रूप से यह नहीं दर्शाता है कि विकलांग दावेदार को अपने पूरे जीवन में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इस गंभीर दुर्घटना से 45 वर्षीय बुजुर्ग के सपने और भविष्य की उम्मीदें धूमिल हो गईं। दावेदार की ख़राब हालत का असर निश्चित रूप से उसके परिवार के सदस्यों पर पड़ा है। दावेदार को पूर्णकालिक देखभाल प्रदान करने की आवश्यकता के कारण उनके संसाधनों और ताकत पर दबाव पड़ना स्वाभाविक है। अपीलार्थी द्वारा उत्तेजना और समर्थन के लिए लगातार उन पर निर्भर रहना सभी हितधारकों के लिए भावनात्मक, शारीरिक और वित्तीय थकान पैदा करना तय है।

मोटर वाहन अधिनियम सामाजिक कल्याण कानून की प्रकृति में है और इसके प्रावधान यह स्पष्ट करते हैं कि मुआवजा उचित रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए। "हेलेन सी. रेबेलो और अन्य बनाम महाराष्ट्र एसआरटीसी और अन्य"1999 (1) एससीसी 90 में प्रकाशित में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने 'न्यायसंगत' मुआवजे की रूपरेखा पर निम्नलिखित विचार रखे हैं,

> "शब्द "न्याय", अपने नामकरण के रूप में, एक बड़े परिधीय क्षेत्र के साथ समानता, निष्पक्षता और तर्कसंगतता को दर्शाता है। निस्संदेह, विशालता मनमानी नहीं है; यह विवेक द्वारा प्रतिबंधित है जो उचित और न्यायसंगत है, यदि यह इससे अधिक है; इसे न्यायसंगत ही नहीं अनुचित, अतार्किक, असमान भी कहा जाता है।"

अतः एक व्यक्ति को न केवल दुर्घटना के कारण लगी चोट के लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए, बल्कि चोट के कारण हुए नुकसान और जीवन बदलने वाली घटना से पहले वह जीवन जीने में उसकी असमर्थता के लिए भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। "जगदीश बनाम मोहन और अन्य"2018(4) एससीसी 571 में प्रकाशित मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने मानव जीवन और गरिमा के आंतरिक मूल्य पर निम्नलिखित प्रासंगिक टिप्पणी की, जिसे मान्यता देने का प्रयास किया गया है:

> "...मुआवज़े को प्राणी की गरिमा को बहाल करने के लिए कानून के वास्तविक प्रयास को प्रतिबिंबित करना चाहिए। मुआवज़े के हमारे पैमाने इतने ख़राब नहीं होने चाहिए कि कोई यह प्रश्न उठाए कि क्या हमारा

कानून मानव जीवन को महत्व देता है। यदि ऐसा होता है, जैसाकि होना भी चाहिए, तो इसे नुकसान के दर्द और पीड़ा के आघात के लिए एक यथार्थवादी प्रतिपूर्ति प्रदान करनी होगी। मुआवजे का पंचाट कानून की खैरात नहीं है। अधिकारों की चर्चा में, वे कानून के तहत अधिकार का गठन करते हैं।

न्यायालयों को जीवन की वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए, विकलांगता की सीमा के आकलन और दावेदार की आय सृजन क्षमता सहित इसके प्रभाव दोनों के संदर्भ में यथार्थवादी मुआवजा प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए।

किसी विकलांगता से उत्पन्न आर्थिक हानि की सीमा को स्थायी विकलांगता की सीमा के अनुपात में नहीं मापा जा सकता है। इस पहलू को माननीय उच्चतम न्यायालय ने "राज कुमार बनाम अजय कुमार और अन्य" 2011 (1) एससीसी 343 में प्रकाशित में देखा कि: -

"10. जहां दावेदार चोटों के परिणामस्वरूप स्थायी विकलांगता से पीड़ित होता है, भविष्य की कमाई के नुकसान के तहत मुआवजे का आकलन उसकी कमाई क्षमता पर ऐसी स्थायी विकलांगता के प्रभाव और प्रभाव पर निर्भर करेगा। न्यायाधिकरण को यांत्रिक रूप से स्थायी विकलांगता के प्रतिशत को आर्थिक हानि या कमाई क्षमता के नुकसान के प्रतिशत के रूप में लागू नहीं करना चाहिए। अधिकांश मामलों में, स्थायी विकलांगता से उत्पन्न आर्थिक हानि का प्रतिशत, अर्थात कमाई क्षमता के नुकसान का प्रतिशत, स्थायी विकलांगता के प्रतिशत से भिन्न होगा। कुछ न्यायाधिकरण गलत मानते हैं कि सभी मामलों में, स्थायी विकलांगता की एक विशेष सीमा (प्रतिशत) के परिणामस्वरूप कमाई क्षमता का नुकसान होगा, और परिणामस्वरूप, यदि प्रस्तुत साक्ष्य 45% को स्थायी विकलांगता के रूप में दिखाता है, तो माना जाएगा कि 45% है भविष्य की कमाई क्षमता का नुकसान। अधिकांश मामलों में, कमाई क्षमता के नुकसान की सीमा (प्रतिशत) को स्थायी विकलांगता की सीमा (प्रतिशत) के बराबर करने पर या तो बहुत कम या बहुत अधिक मुआवजा दिया जाएगा।

11. न्यायाधिकरण द्वारा कमाई की क्षमता पर स्थायी विकलांगता के प्रभाव का आकलन करने की आवश्यकता है; और आय के प्रतिशत के संदर्भ में कमाई क्षमता के नुकसान का आकलन करने के बाद, कमाई के भविष्य के नुकसान पर पहुंचने के लिए इसे पैसे के संदर्भ में मात्राबद्ध करना होगा (निर्भरता के नुकसान को निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली मानक गुणक विधि को लागू करके)। हालाँकि, हम ध्यान दे सकते हैं कि कुछ मामलों में, साक्ष्य और मूल्यांकन करने पर, न्यायाधिकरण को पता चल सकता है कि स्थायी विकलांगता के परिणामस्वरूप कमाई क्षमता के नुकसान का प्रतिशत स्थायी विकलांगता के मामले में लगभग प्रतिशत के समान है 4(2011)1 एससीसी 343, निश्चित रूप से, न्यायाधिकरण मुआवजे के निर्धारण के लिए उक्त प्रतिशत को अपनाएगा।

भविष्य की कमाई क्षमता पर स्थायी विकलांगता के प्रभाव को निर्धारित करने के लिए परीक्षण में निम्नलिखित 3 चरण शामिल हैं जैसाकि राज कुमार (सुप्रा.) में निर्धारित किया गया था और माननीय उच्चतम न्यायालय ने "चनप्पा नागप्पा मुचलगोडा बनाम डिवीजनल मैनेजर, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी" लिमिटेड" ने 2020 (1) एससीसी 796 में दोहराया था कि:-

"13. वास्तविक कमाई क्षमता पर स्थायी विकलांगता के प्रभाव का पता लगाने में तीन चरण शामिल हैं। न्यायाधिकरण को पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि दावेदार स्थायी विकलांगता के बावजूद कौन सी गतिविधियाँ कर सकता है और स्थायी विकलांगता के परिणामस्वरूप वह क्या नहीं कर सकता है (यह जीवन की सुविधाओं के नुकसान के तहत मुआवजा देने के लिए भी प्रासंगिक है) दूसरा कदम दुर्घटना से पहले उसके व्यवसाय, पेशे और काम की प्रकृति, साथ ही उसकी उम्र का पता लगाना है। तीसरा चरण यह पता लगाना है कि क्या (i) दावेदार किसी भी प्रकार की आजीविका कमाने में पूरी तरह से अक्षम है, या (ii) क्या स्थायी विकलांगता के बावजूद, दावेदार अभी भी उन गतिविधियों और कार्यों को प्रभावी ढंग से कर सकता है, जो वह था पहले जारी रखना, या

(iii) क्या उसे अपनी पिछली गतिविधियों और कार्यों का निर्वहन करने से रोका या प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन वह कुछ अन्य या कम पैमाने की गतिविधियों और कार्यों को जारी रख सकता है ताकि वह कमाता रहे या अपनी आजीविका कमाता रहे।

"पप्पू देव यादव बनाम नरेश कुमार और अन्य" 2020 एससीसी ऑनलाइन 752 में प्रकाशित में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त मानदंड की पुष्टि की गई थी। निम्नलिखित तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निर्धारित किया गया था:

"13. तथ्यात्मक विवरण से पता चलता है कि अपीलार्थी, एक 20 वर्षीय डेटा एंट्री ऑपरेटर (जिसने 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी) को स्थायी विकलांगता का सामना करना पड़ा, अर्थात उसका दाहिना हाथ कट गया (जो कट गया था)। विकलांगता 89% आंकी गई थी। हालाँकि, न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय ने विकलांगता का पुनर्मूल्यांकन केवल 45% किया, इस धारणा पर कि मुआवजे के लिए मूल्यांकन एक अलग आधार पर होना था, क्योंकि चोट के कारण केवल एक हाथ का नुकसान हुआ था। इस न्यायालय की राय में, यह दृष्टिकोण पूरी तरह से यांत्रिक है और वास्तविकताओं को पूरी तरह से नजरअंदाज करता है। हालांकि, यह सच है कि एक अंग या एक हिस्से की चोट के आकलन से पूरे शरीर पर स्थायी चोट नहीं लग सकती है, न्यायालय को जो जांच करनी है वह परिणामी हानि है जो चोट के कारण कमाई या आय पैदा करने की क्षमता पर निर्भर करती है। इस प्रकार, ड्राइविंग या ऐसा कुछ जिसमें पैदल चलना या निरंतर गतिशीलता शामिल है, जैसे व्यवसाय करने वाले किसी व्यक्ति के एक पैर की हानि के परिणामस्वरूप गंभीर आय उत्पन्न करने वाली हानि होती है या यह पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। इसी तरह, बढ़ई या हेयरड्रेसर, या मशीनिस्ट जैसी नौकरी में शामिल व्यक्ति और उस पर अनुभवी व्यक्ति के लिए, एक हाथ की हानि, (विशेषकर एक कार्यात्मक हाथ) आय सृजन के लगभग विलुप्त होने की ओर ले जाती है। अगर पीड़ित की उम्र 40 से अधिक हो तो पुनर्वास की गुंजाइश भी कम हो जाती है। ये व्यक्तिगत कारक अत्यंत

महत्वपूर्ण हैं जिन्हें कमाई क्षमता के नुकसान के आकलन के उद्देश्य से स्थायी विकलांगता की सीमा निर्धारित करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।

"20. न्यायालयों को रूढ़िवादी या अदूरदर्शी दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि विकलांगता की सीमा के आकलन और विभिन्न मदों के तहत मुआवजे दोनों में मामले को जीवन की वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए देखना चाहिए। वर्तमान मामले में, न्यायालय की राय में, एक हाथ की हानि के परिणामस्वरूप अपीलार्थी को आय अर्जित करने में गंभीर हानि हुई। एक टाइपिस्ट/डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में, उनके हाथों का पूर्ण कामकाज उनकी आजीविका के लिए आवश्यक था। उनकी स्थायी विकलांगता की सीमा 89% आंकी गई थी; हालाँकि, उच्च न्यायालय ने कुछ 'आनुपातिक' सिद्धांत के पूरी तरह से गलत अनुप्रयोग पर इसे आधा करके 45% कर दिया, जो अतार्किक था और कानून में समर्थन योग्य नहीं है। जो देखा जाना चाहिए, जैसाकि निर्णय के बाद निर्णय पर जोर दिया जाता है, पीड़ित की आय पैदा करने की क्षमता पर चोट का प्रभाव पड़ता है। किसी अंग (एक पैर या बांह) की हानि और उस कारण इसकी गंभीरता का आकलन पीड़ित के पेशे, व्यवसाय या व्यवसाय के संबंध में किया जाना चाहिए; तैयार प्रयोग के लिए कोई अंधा अंकगणितीय फार्मूला नहीं हो सकता। पिछले निर्णयों में उल्लिखित सिद्धांतों के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी की आय सृजन क्षमता निस्संदेह गंभीर रूप से प्रभावित हुई थी। शायद, यह 89% की सीमा तक नहीं है, यह देखते हुए कि वह अभी भी एक हाथ का उपयोग करता है, युवा है और अभी भी, उम्मीद है कि वह किसी अन्य व्यवसाय के लिए खुद को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित (और पुनर्वासित) कर रहा है। फिर भी, विकलांगता का आकलन 45% नहीं हो सकता; इस मामले की परिस्थितियों में इसका मूल्यांकन 65% किया गया है।"

"गोविंद यादव बनाम द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड"2011 (10) एससीसी 683 में प्रकाशित में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि:

"18. हमारे विचार में, मुआवजे की मात्रा निर्धारित करने में सभी न्यायाधिकरणों और उच्च न्यायालयों द्वारा अरविंद कुमार मिश्रा बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (सुप्रा.) और राज कुमार बनाम अजय कुमार (सुप्रा.) में निर्धारित सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। दुर्घटना के पीड़ितों को देय, जो स्थायी या अस्थायी रूप से विकलांग हैं। यदि दुर्घटना का शिकार व्यक्ति स्थायी विकलांगता से पीड़ित है, तो न केवल शारीरिक चोट और उपचार के लिए, बल्कि कमाई के नुकसान और सामान्य जीवन जीने और सुविधाओं का आनंद लेने में असमर्थता के लिए भी पर्याप्त मुआवजा देने का प्रयास किया जाना चाहिए।

(बल दिया गया)

"के. सुरेश बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड"2012 (12) एससीसी 724, में प्रकाशित मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि:-

"10. यह बताना उल्लेखनीय है कि मुआवजे की मात्रा का निर्धारण करते समय एक न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को घायल व्यक्ति की पीड़ाओं को ध्यान में रखना होगा जिसमें पूर्ण जीवन जीने में उसकी असमर्थता, सामान्य सुविधाओं का आनंद लेने में उसकी असमर्थता शामिल होगी जिसका वह आनंद ले सकता था। लेकिन चोटों और उसकी उतना कमाने की क्षमता के लिए, जितना वह कमाता था या कमा सकता था। अतः, मुआवजे की गणना करते समय न्यायाधिकरण या न्यायालय का दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए। कहने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ अनुमान शामिल होंगे क्योंकि मुआवजे की मात्रा निर्धारित करने के लिए कोई गणितीय सटीकता या सटीक सूत्र नहीं हो सकता है। मुआवज़े के निर्धारण में 'न्यायसंगत मुआवज़े' की बुनियादी कसौटी अंतर्निहित होनी चाहिए।"

(बल दिया गया)

इस न्यायालय ने पाया कि अपीलार्थी को दिया गया मुआवजा अपर्याप्त है।

अपीलार्थी 83.2% स्थायी विकलांगता से पीड़ित है और उसे 'जीवन में भविष्य की सुविधाओं की हानि' और 'भविष्य की संभावनाओं की हानि' के मद में एक पैसा भी नहीं दिया गया है, अतः, आक्षेपित पंचाट में उपयुक्त वृद्धि की आवश्यकता है। रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के मद्देनजर, अपीलार्थी-दावेदार निम्नलिखित शर्तों में मुआवजा पाने का पात्र है: -

मासिक आय	3450 X 83/100 रुपए = 2863.5/- रुपए
वार्षिक आय	2863.5 x12 रुपए = 34,362/- रुपए प्रतिवर्ष
गुणक लागू किया जाना है	14 34,362 X 14 = 4,81,068/- रुपए
25% भविष्य की संभावनाएं जोड़ें	4,81,068 रुपए + 1,20,267 रुपए = 6,01,335/- रुपए
चिकित्सा व्यय जोड़ें	1,00,000/- रुपए
परिवहन व्यय जोड़ें	25,000/- रुपए
अस्पताल शुल्क जोड़ें	600 रुपए (प्रतिदिन) X 152 (दिन)= 91,200/-
जीवन में सुख-सुविधाओं की हानि जोड़ें	3,00,000/- रुपए
कुल मुआवजा देय	11,17,535/- रुपए
न्यायाधिकरण द्वारा कम राशि प्रदान की गई	11,17,535 रुपए - 5,22,950 रुपए = 5,94,585/- रुपए
मुआवज़े की बढ़ाई गई राशि	5,94,585/- रुपए

उपरोक्त के मद्देनजर, अपीलार्थी-दावेदार 5,94,585/- रुपये, की अतिरिक्त राशि प्राप्त करने का पात्र होगा। जिस पर दावा याचिका दायर करने की तारीख से वास्तविक भुगतान होने तक 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगेगा।

परिणामस्वरूप, अपील का निपटारा किया जाता है। बढ़े हुए मुआवज़े का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा इस निर्णय के छह सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाएगा। न्यायाधिकरण दावेदार के बचत बैंक लेखे में 2,00,000/- रुपये का भुगतान करेगा और बढ़े हुए मुआवजे की शेष राशि तीन वर्ष की अवधि के लिए किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में निवेश की जाएगी और जमा पर अपीलार्थी को मासिक आधार पर अर्जित ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड तुरंत वापस भेजा जाए।

(अनूप कुमार ढंड), न्यायमूर्ति

HEENA GANDHI /14

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल**,** द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।